भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 26

उत्तर देने की तारीखः 29.11.2021

साक्षरता दर के मामले में पुरूषों और महिलाओं में अंतर

†**26. श्रीमती संध्या राय:**
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री पी.पी.चौधरी:
श्री राजबहादुर सिंह:
श्री कृष्णपाल सिंह यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में साक्षरता दर के मामले में पुरूषों और महिलाओं में सबसे अधिक अंतर है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या उक्त राज्यों में स्त्री पुरूष साक्षरता के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ड.) क्या महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों में स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) उपरोक्त राज्यों के स्कूलों में लड़कियों के नामांकन के जिलेवार आंकड़े क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): जुलाई 2017-जून 2018 के दौरान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए एनएसएस 75वें दौर के सर्वेक्षण की एनएसएस रिपोर्ट संख्या 585 (75/25.2/1) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर इस प्रकार है:

राज्य	पुरुष	महिला
उत्तर प्रदेश	81.8	63.4
मध्य प्रदेश	81.2	65.5
राजस्थान	80.8	57.6

(ख) से (घ): देश में साक्षरता दर में सुधार के लिए, साक्षर भारत की योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 26 राज्यों के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में और एक संघ राज्य क्षेत्र में लागू की गई थी, 2001 की जनगणना के अनुसार जहां वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और इससे कम थी और जिसमें महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके अलावा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में समग्र शिक्षा - एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाया गया है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

(ड़): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूली शिक्षा के संकेतकों पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) सिस्टम विकसित किया है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) 2019-20 और अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2018-19 और 2017-18 में लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात निम्नानुसार है:

लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (अखिल भारतीय)

वर्ष	प्राथमिक (I-V)	उच्च प्राथमिक (VI-VIII)	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्च शिक्षा
2019-20	103.69	90.46	77.83	52.40	27.1
2018-19	107.78	88.54	76.93	50.84	26.3
2017-18	103.03	89.34	76.23	48.32	25.8

(च): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के स्कूलों में लड़कियों के नामांकन के लिए जिलेवार आंकड़े वेब लिंक https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/reportDashboard/sReport रिपोर्ट संख्या 4004 से प्राप्त किए जा सकते हैं।

*****